

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ० ए० संख्या 867/2019 वाद डा० विकास खुराना, अध्यक्ष इतिहास विभाग एस०एस०पी०जी० कालेज एवं डा० आलोक सिंह, अध्यक्ष, रसायन शास्त्र विभाग, शाहजहाँपुर बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 की अनुपालन आख्या

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में डा० विकास खुराना, अध्यक्ष इतिहास विभाग एस०एस०पी०जी० कालेज एवं डा० आलोक सिंह, अध्यक्ष, रसायन शास्त्र विभाग, शाहजहाँपुर द्वारा संयुक्त रूप से, पौराणिक नदी गंरा/देवह में चल रहे नियम विरुद्ध खनन के सम्बन्ध में की गयी शिकायत दिनांक 04.06.2019 का संज्ञान लेते हुये वाद संख्या ओ० ए० संख्या 867/2019 में डा० विकास खुराना, अध्यक्ष इतिहास विभाग एस०एस०पी०जी० कालेज एवं डा० आलोक सिंह, अध्यक्ष, रसायन शास्त्र विभाग, शाहजहाँपुर बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश में दिनांक 30.10.2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं-

"..... Let the district Magistrate, Shahjahanpur and U.P State Pollution Control Board (State PCB) look into the matter and take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report to this Tribunal within one month from the date of receipt of copy of this order by e-mail at judicial-ngt@gov.in. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

A copy of this order, along with complaint, be sent to the east District Magistrate, Shahjahanpur and State PCB by e-mail for compliance. Needless to say that order of National Green Tribunal is binding as a degree of Court and non-compliance is actionable by the way of punitive action including prosecution, in terms of the National Green Tribunal Act, 2010

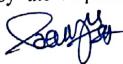
List for further consideration on 20.02.2020

उक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) शाहजहाँपुर के पत्र संख्या 1674/एस०टी०/(वि./रा.)-2020 दिनांक 07.02.2020 द्वारा जिला खनन अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं (संलग्नक-1) तत्क्रम में उक्त संबन्धित शिकायती प्रकरण में उल्लिखित तथ्यों तथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नवत हैं-

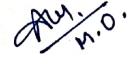
1. इस संबन्ध में अवगत कराना है कि जनपद शाहजहाँपुर में ई-टेण्डर सह ई-नीलामी के माध्यम से साधारण बालू का एक मात्र खनन पट्टा मै० विराट कान्स्ट्रक्शन्स मो० तारीन बहादुर गंज तहसील सदर शाहजहाँपुर के पक्ष में ग्राम शहर खास मु० वरती बेगम तहसील सदर में दिनांक 15.02.2018 से 05 वर्ष हेतु 1,09,245 घनमी० बालू खनन की मात्रा प्रतिवर्ष के लिये स्वीकृत हुआ था। पट्टेधारक द्वारा किरातों की धनराशि जमा न किये जाने तथा पट्टा विलेख में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न किये जाने के कारण तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश संख्या 1109/डी०एल०आर०सी० (खनन अनुभाग) 2019 दिनांक 31.05.2019 से पट्टा निरस्त करते हुये पाँच वर्ष के लिये पट्टाधारक को काली सूची में डाला गया है (संलग्नक-2), जिससे भुख होकर पट्टेधारक द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 21236/2019 मै० विराट कान्स्ट्रक्शन्स व अन्य बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य योजित की गयी।

उक्त रिट याचिका में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 08.07.2019 को आदेश पारित किया गया जिसका मुख्यांश निम्नवत है-

"Since in the fact of the present case, there is a complete failure to follow due process, we find ourselves unable to sustain the order dated 31.05.2019 and the recovery certificate dated 01.06.2019 passed by the respondent no 02 (Annexure no 4&5 to the writ petition respectively)"







“We accordingly allow the writ petition and quash the order dated 31.05.2019 and the recovery certificate dated 01.06.2019. We further clarify that in case the respondents do choose to initiate fresh proceedings for blacklisting the firm of the petitioner we leave it upon to them to do so subject to the observation that the proceeding if initiated shall be undertaken in accordance with law and the observation appearing herein above.” (संलग्नक-3)

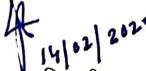
2. पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही, पट्टा विलेख की रातों ,सीमा स्तम्भ सुरक्षित नहीं रखने, 30 दिनों में से मात्र 14 दिनों की सी0सी0टी0वी0 कैमरे की डी0वी0आर0 रिकार्डिंग सुरक्षित रखने तथा समय पर किस्तों का भुगतान नहीं किये जाने जैसी अनियमितताओं पाये जाने पर की गयी थी। तत्समय भी अवैध खनन या मशीनों आदि से खनन किये जाने की शिकायत नहीं थी।
3. उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 31.05.2019 के बाद एक मात्र चल रहे बालू खनन पट्टा को निरस्त करने के उपरान्त वर्तमान में एक भी खनन पट्टा संचालित नहीं है ना ही कोई खनन कार्य नदी में किया जा रहा है।
4. पौराणिक नदी गर्गा/देवहा में चल रहे नियम विरुद्ध खनन के संबन्ध में खान अधिकारी शाहजहाँपुर व उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिनांक 14.02.2020 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पौराणिक नदी गर्गा/देवहा नदी क्षेत्र में बालू खनन कार्य होता हुआ नहीं पाया गया और ना ही खनन कार्य में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी आदि खनन क्षेत्र में पाया गया।
5. निरीक्षण के समय पौराणिक नदी गर्गा/देवहा नदी में जल का प्रवाह किसी तरह प्रभावित होता हुआ नहीं पाया गया।

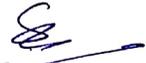
इस प्रकार शिकायतकर्ता की शिकायत तथ्यों से संबन्धित नहीं है। वर्तमान में पौराणिक नदी गर्गा/देवहा में कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है और नाही मशीनों आदि से कोई खनन ही किया जा रहा है। अनाधिकृत खनन की शिकायत प्राप्त होने पर तथा प्रवर्तन कार्यवाही में यदि कोई खनन या परिवहन पाया जाता है, तो दोषियों के विरुद्ध विधिक दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


(पी0सी0 कनौजिया)
वैज्ञानिक सहायक
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बरेली


(जितेन्द्र लाल)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बरेली


(डा0 अभय रंजन)
खान अधिकारी
शाहजहाँपुर


क्षेत्रीय, अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बरेली


जिलाधिकारी
शाहजहाँपुर

कार्यालय

जिलाधिकारी

शाहजहाँपुर।

पत्रांक 1674 / एस0टी0 / (वि./रा.)-2020

दिनांक: 07 फरवरी, 2020

विषय : पौराणिक नदी गर्गा/देवह में चल रहे नियम विरुद्ध खनन के सम्बन्ध में।

खनन अधिकारी,
शाहजहाँपुर।

उपर्युक्त विषयक मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में डा0 विकास खुराना, अध्यक्ष इतिहास विभाग एस0एस0पी0जी0 कालेज द्वारा दिनांक 04.06.2019 को पौराणिक नदी गर्गा/देवह में चल रहे नियम विरुद्ध खनन के सम्बन्ध में शिकायत ओ0ए0 संख्या-867/2019 द्वारा निर्देशित किया गया है कि पौराणिक नदी गर्गा/ देवह नदी में चल रहे खनन में अवैध/अवैज्ञानिक तरीके से जनपद शाहजहाँपुर में प्रवाहित गर्गा नदी में किये जा रहे खनन पर जिलाधिकारी शाहजहाँपुर तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही कर एक माह के अन्दर ई-मेल के माध्यम से सूचना चाही गयी है।

उक्त के सन्दर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया प्रकरण के सम्बन्ध में जांच कर कार्यवाही करते हुये सूचना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बरेली को भिजवाते हुये कृत कार्यवाही अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- यथोक्त।

07.02.2020

अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)
शाहजहाँपुर।

Ram

Del
PES

J

मै0 विराट कान्स्ट्रक्शन,
मि0 मो0 तारीन बहादुरराज,
शाहजहाँपुर।

खनन पट्टा निरस्तीकरण आदेश

आप अवगत है, कि आपको कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहाँपुर के पत्र संख्या-966 (1)/डी0एल0आर0सी0/2019 दिनांक 16 फरवरी, 2019 द्वारा पट्टाविलेख की शर्तों तथा सीमा स्तम्भ सुरक्षित नहीं रखने, 30 दिनों में से मात्र 14 दिनों की सी0सी0टी0वी0 कैमरे की डी0वी0आर0 रिकॉडिंग सुरक्षित रखने, जानबूझकर कैमरों को इस प्रकार सेट करना जिससे आने-जाने वाली गाड़ियों के नम्बर न दिखाई देने, बिना वैध प्रपत्र एम0एम0-11 के माध्यम से बालू का परिवहन किये जाने, जांच के समय मौके पर पाये गये बाहनों का इन्ट्री रजिस्ट्रार एवं डी0वी0आर0 से मिलान सम्बन्ध नहीं होने तथा समय पर किशतों का मुगतान नहीं किये जाने जैसी अनियमितताओं के संबंध में कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में आप द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 08-03-2019 में उल्लिखित तथ्यों का अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा परीक्षण किया गया। उक्त कमेटी द्वारा परीक्षणोपरान्त अपनी आख्या दिनांक 24-04-2019 में आप द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न पाते हुए पूर्व में हुई जांच में पाई गई अनियमितताओं की पुष्टि की गई है।

जनपद शाहजहाँपुर की तहसील सदर स्थित ग्राम शहर खास मु0 बरती वेगम, गार्स नदी तल में स्थित गाटा सं0 46, 52, 61,54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 73, 79 मि0,76, 67मि0 68 मि0,45, 47,48, 49, 50, 44,33/1.34/1.32/1.40,41,42,43, कुल 34 किता/ क्षेत्रफल 7.283 हे0, पर 109245 घन मीटर साधारण बालू प्रतिवर्ष निकारी हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से 05 वर्ष हेतु दिनांक 07.11.2017 के शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया था। आप द्वारा पट्टा संचालन में बरती गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 966 (एक)/डी0एल0आर0 सी0/2019 दिनांक 16.02.2019 द्वारा आपको कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 08-3-2019 के माध्यम से उक्त कारण बताओ नोटिस का विन्दुवार स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके क्रम में कार्यालय आदेश संख्या 995/डी0एल0आर0सी0/2019 दिनांक 11-03-2019 के अन्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 08-3-2019 का परीक्षण अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) शाहजहाँपुर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति ने अपनी जांच आख्या दिनांक 24-4-2019 उपलब्ध करायी जिसमें आप पर लगाये गये सभी 06 आरोप सिद्ध पाये गये।

साथ ही समिति द्वारा यह पाया गया कि आप द्वारा वार्षिक पट्टा धनराशि की प्रथम वर्ष की चतुर्थ किशत की अवशेष धनराशि अंकन रू0 6495995.00 एवं द्वितीय वर्ष की प्रथम किशत की धनराशि अंकन रू0 18145595.00 अतः कुल धनराशि अंकन रू0 24641590.00, जो नियमतः दिनांक 01 जनवरी, 2019 तक जमा की जानी चाहिए थी, अभी तक जमा नहीं की गई है। आप द्वारा द्वितीय वर्ष की द्वितीय किशत रू0 18145595.00 जो दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को जमा की जानी चाहिए थी, जमा नहीं की गयी आप द्वारा कुल अवशेष धनराशि रू0 4,27,87,185.00 में से मात्र रू0 30.00 लाख जमा किया गया। अवशेष धनराशि अंकन रू0 3,97,87,185.00 जमा न करने के कारण आप द्वारा पट्टा शर्तों के प्रतरत भाग-2 (1) का उल्लंघन किया गया है। आप द्वारा पूर्व में भी 01 जुलाई, 2018 को देय किशत विलम्ब से जमा किया गया तथा अक्टूबर 2018 को देय किशत को भी पूरा जमा नहीं किया गया। 01 जनवरी, 2019 को देय किता भी आप द्वारा समय पर जमा नहीं की गयी जोकि पट्टा विलेख की शर्त भाग-2 (3) का उल्लंघन है। उपरो उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम-58 के अनुसार नोटिस तामील होने के 15 दिन के पर्याप्त खनन पट्टा समाप्त किया जा सकता है तथा भू-राजस्व के बकाया के रूप बरसू किया जायेगा। नियमावली 1963 के नियम-60 के अनुसार राज्य सरकार पट्टेदार को अपना मामला बुकित-युक्त अवसर प्रदान करने के पर्याप्त समाप्ति के साथ तथा दो वर्ष से अनाधिक एसी अवधि के लिये काली सूची में डाल दिया जायेगा जो विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा और उक्त अवधि के दौरान आपको इस नियमावली के अधीन कोई खनिज परिहार स्वीकृत नहीं किया जायेगा। चूंकि आप द्वारा स्वामित्व का मुगलान समय पर न करने के कारण नियम-58 के दोषी हैं। आपको क्रमशः दिनांक 22.10.2018, 15.12.2018, 31.01.2019, 16.02.2019 तथा दिनांक 27-04-2019 को पाँच बार स्वामित्व की धनराशि जमा करने हेतु नोटिस तामील कराया गया, परन्तु उसके पर्याप्त भी आप द्वारा आज तक अवशेष धनराशि जमा नहीं की गयी। दिनांक 22.04.2019 को आप द्वारा लिखित अनुरोध किया गया कि आप अवशेष

(Handwritten Signature)

(Handwritten Mark)

धनराशि को दिनांक 30, मई, 2019 तक जमा कर देंगे। जिसके आधार पर कमेटी द्वारा आपको अवशेष धनराशि जमा करने हेतु पर्याप्त समय दिनांक 30, मई, 2019 तक दिए जाने की संस्तुति की गयी, फिर भी आप द्वारा दिनांक 30, मई, 2019 तक धनराशि जमा नहीं की गयी है तथा सरकारी राजस्व जमा न करके प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास किया गया।

अतएव नोटिस क्रमशः दिनांक 22.10.2018, 15.12.2018, 31.01.2019, 16.02.2019 तथा दिनांक 27.4.2019 द्वारा किरत की बकाया धनराशि अंकन ₹ 3,97,87,165.00 (तीन करोड़, सत्ताने लाख, सत्तासी हज़ार, एक सौ पच्चासी) मात्र अनुमन्य अवधि के अन्दर पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद आप धनराशि जमा करने में विफल रहे जिसके कारण आपके पक्ष में प्रस्तर-एक में वर्णित भूमि के लिए स्वीकृत खनन पट्टे को, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-58 में विनिहित शक्ति का उपयोग कर समय पूर्व एतद्वारा समाप्त किया जाता है।

खनन पट्टा समय पूर्व समाप्त हो जाने के फलस्वरूप खनन पट्टे की शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्रतिभूति की मद में जमा धनराशि ₹ 1,64,95,995.00 (एक करोड़ चौंसठ लाख, पच्चानवे हज़ार, नौ सौ पच्चानवे) मात्र राज्य सरकार के पक्ष में जम्मा किया जाता है तथा खनन पट्टे की किरतों की बकाया धनराशि ₹ 2,16,41,590.00 (दो करोड़, सोलह लाख, इकतालिश हज़ार, पाँच सौ नब्बे) एवं दिनांक 01, अप्रैल, 2019 को देय द्वितीय वर्ष की चतुर्थ किरत में से माह मई एवं जून, 2019 हेतु धनराशि ₹ 1,20,97,063.30 (एक करोड़, बीस लाख, सत्ताने हज़ार, तिरसठ. रूप्ये तीस पैसे) मात्र जोड़कर कुल धनराशि ₹ 3,37,38,653.30 (तीन करोड़, सैंतिस लाख, अड़तिस हज़ार, छः सौ तिरपन रूप्ये तीस पैसे मात्र) तथा कुल देय रॉयल्टी पर 10 प्रतिशत खनिज न्यास निधि ₹ 0 अंकन 33,73,865.33 (तीस लाख, तिहत्तर हज़ार, आठ सौ पैंसठ रूप्ये तैतीस पैसे मात्र) तथा 02 प्रतिशत टी0डी0एस0 ₹ 0 अंकन 06,74,773.06 (छः लाख चौहत्तर हज़ार, सात सौ तिहत्तर रूप्ये छः पैसे मात्र) नोटिस के दिनांक से बकाया धनराशि उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली के नियम-58 के तहत देय धनराशि पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के साथ वसूल किए जाने हेतु वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर पट्टाधारक का पट्टा निरस्त करते हुए उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली के नियम-60 के अन्तर्गत मै0 विराट कान्ट्रिब्यूशन प्रो0 श्री प्रिंस गुप्ता, नि0 मै0 तारीन बहादुरगंज, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश का नाम 05 वर्ष (पांच वर्ष) की अवधि के लिए काली सूची में डाला जाता है।

(अमृत त्रिपाठी)
जिलाधिकारी,
शाहजहाँपुर।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर।
- 6- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक यानिकी प्रभाग, शाहजहाँपुर।
- 7- उप जिलाधिकारी सदर, शाहजहाँपुर।
- 8- नोडल प्रभारी, ई0एम0एम0-11, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, लखनऊ को पट्टेधारक के पक्ष में निर्गत ई-एम0एम0-11 की डाटा इण्ट्री स्थायीरूप से प्रतिबधित किए जाने हेतु।

(अमृत त्रिपाठी)
जिलाधिकारी,
शाहजहाँपुर।

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

बस्ती प्रमाण-पत्र
(नियम-58, नियमावली-1963)

कलेक्टर,
शाहजहाँपुर।

मैसर्स विराट कान्स्ट्रक्शन, मो० तारिन बहादुरगंज शाहजहाँपुर, को जनपद-शाहजहाँपुर की तहसील सदर स्थित ग्राम शहर खास मु० बस्ती वेगम, गरा नदी तल में स्थित गाटा सं० 46, 52, 61, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 73, 79 मि०, 76, 67 मि० 68 मि०, 45, 47, 48, 49, 50, 44, 33/1.34/1.32/1.40, 41, 42, 43, कुल 34 किता/क्षेत्रफल 7.283 हे०, पर 109245 घन मीटर साधारण बातू प्रतिवर्ष निकासी हेतु ई-निविदा सह ई-नौलामी प्रणाली के माध्यम से 05 वर्ष हेतु तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 07.11.2017 के अन्तर्गत विभिन्न शर्तों के अधीन स्वीकृत खनन पट्टा स्वीकृत किया गया था।

पट्टाधारक द्वारा पट्टा विलेख की शर्तों का उल्लंघन करने तथा निर्धारित वार्षिक पट्टा धनराशि की बकाया किशतों को जमा न किए जाने के कारण उक्त पट्टा समयपूर्व समाप्त करते हुए मैसर्स विराट कान्स्ट्रक्शन, मो० तारिन बहादुरगंज शाहजहाँपुर के विरुद्ध निम्नानुसार देय बकाया धनराशि की बस्ती-अपेक्षित है :-

क्र०सं०	बकाया-का विवरण	बस्ती हेतु धनराशि
1	2	5
1	दिनांक 01.04.2018 को प्रथम वर्ष की देय रॉयल्टी की द्वितीय किस्त रु० 1,64,95,995.00/- को विलम्ब से जमा करने के कारण उस पर दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से 01 जून 2018 तक (02 माह) के व्याज की धनराशि रु० 4,94,879.85 में से रु० 1,30,160.00 जमा के पश्चात अवशेष धनराशि।	3,64,719.85
2	दिनांक 01.07.2018 को प्रथम वर्ष की देय रॉयल्टी की तृतीय किस्त रु० 1,64,95,995.00/- को विलम्ब से जमा करने के कारण उस पर दिनांक 01 जुलाई, 2018 से 26 सितम्बर, 2018 तक (02 माह 26 दिन - कुल 88 दिवस) के व्याज की धनराशि।	7,15,880.98
3	दिनांक 01.10.2018 को प्रथम वर्ष की देय रॉयल्टी की चतुर्थ किस्त रु० 1,64,95,995.00/- में से रु० 01 करोड़ मात्र को विलम्ब से जमा करने के कारण उस पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से 02 जनवरी, 2019 तक (03 माह 02 दिन - कुल 94 दिवस) के व्याज की धनराशि।	4,63,561.64
4	दिनांक 01.10.2018 को प्रथम वर्ष की देय रॉयल्टी की चतुर्थ किस्त रु० 1,64,95,995.00/- में से रु० 30 लाख मात्र को विलम्ब से जमा करने के कारण उस पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से 25 अप्रैल, 2019 तक (06 माह 25 दिन) के व्याज की धनराशि।	3,06,986.30
	कुल व्याज की धनराशि (1+2+3+4)	18,51,148.77
5	दिनांक 01.10.2018 को प्रथम वर्ष की देय रॉयल्टी की चतुर्थ किस्त रु० 1,64,95,995.00/- में से अवशेष धनराशि।	34,95,995.00
6	दिनांक 01.01.2019 को द्वितीय वर्ष की देय रॉयल्टी की प्रथम किस्त।	1,81,45,595.00
7	दिनांक 01.04.2019 को द्वितीय वर्ष की देय रॉयल्टी की द्वितीय किस्त।	1,81,45,595.00
	कुल किस्त की बकाया धनराशि (5+6+7)	3,97,87,185
8	दस प्रतिशत खनिज न्यास निधि की बकाया धनराशि	52,78,717
9	दो प्रतिशत टी०सी०एस० की बकाया धनराशि	10,55,743.40

- क्र०सं०-05 पर दिनांक 01.10.2018 से बकाया धनराशि जमा किए जाने तक 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण व्याज देय होगा।
- क्र०सं०-06 पर दिनांक 01.01.2019 से बकाया धनराशि जमा किए जाने तक 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण व्याज देय होगा।
- क्र०सं०-07 पर दिनांक 01.04.2019 से जमा किये जाने के दिनांक तक 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण व्याज देय होगा।

उक्त बकायेदार की चल/अचल सम्पत्ति जनपद शाहजहाँपुर में स्थित, से उक्त बकाया खनिज देय भू-राजस्व की भांति (बतौर बकाया मालगुजारी) बस्ती होने योग्य है।

अतः उपरोक्त धनराशि बकायादार से भू-राजस्व की भांति (बतौर मालगुजारी) बस्ती कर खनिज विभाग के संचारीपत्रक 0853 अलौह खनन के मद में चालान द्वारा कोषागार में जमा कराकर बस्ती प्रमाण-पत्र घालान राशि एच कॉलम सं०-8 की खनिज न्यास निधि की धनराशि को भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या 37079972007 तथा कॉलम सं०-9 की टी०सी०एस० की धनराशि TAN NO. LKNT07931A में जमा कराकर बस्ती प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को शीघ्र भेजने का कष्ट करें।

Signature *Del*
FREE

(अमृत त्रिपाठी)
जिलाधिकारी,
शाहजहाँपुर।

M. Z. HODA

Advocate High Court

Chamber no - 39

Mob 9450137786

[writ.c]

Civil Misc. writ. Petition No- 21236 of 2019

Distt. Shahjohampur

M/s. Vivat Constructions And Another

vs

State of U.P And 2 others

order dated = 08.07.2019

5-6-17-17

[Handwritten signature]
PBB

4

A.P.R.

Court No. - 4

Case :- WRIT - C No. - 21236 of 2019

Petitioner :- M/S. Virat Constructions And Another

Respondent :- State Of U.P. And 2 Others

Counsel for Petitioner :- Udayan Nandan, Shri Shashi Nandan (Senior Advocate)

Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Bala Krishna Narayana, J.

Hon'ble Prakash Padia, J.

Per: Hon'ble Prakash Padia J.

1. Heard Shri Shashi Nandan learned Senior Advocate assisted by Sri Udayan Nandan learned counsel for the petitioners and Ms. Archana Singh, learned Additional Chief Standing Counsel learned counsel for the respondents.
2. The petitioners have preferred the present writ petition writ challenging the order 31.5.2019 and consequential recovery certificate dated 1/4.6.2019 (Annexure Nos.4 and 5 to the writ petition respectively) passed by the District Magistrate, Shahjahanpur.
3. Facts in brief, as contained in the writ petition are that the petitioners were granted lease on 15th February, 2018 for a period of five years, i.e., from 15.2.2018 to 14.2.2023 at the rate of Rs.604/- per cubic meter for the first year with a stipulation of 10% increase in the said amount in each successive year during the currency of the lease. After the aforesaid lease was granted, the petitioners deposited a sum of Rs.1,64,95,995/- towards security as per the terms of the lease deed. A further amount of Rs.1,64,95,995/- was payable by the petitioners during the first year of the lease period in four equal installments. From the date of execution of the lease deed, the petitioners started excavating the minerals from the area forming part of the lease deed as per the terms and conditions of the lease deed dated 15.2.2018.
4. It is contended in the writ petition that respondent No.2 on a number of occasions orally directed the petitioners to stop the work of



excavation without any rhyme and reason and as such, the petitioners were unable to pay certain installments on time as per the payment schedule of the lease deed, a show-cause notice dated 16.2.2019 was issued by the District Mining Officer/respondent No.3 to the petitioners levelling certain allegations to the effect that the petitioners are executing mining lease in contravention of the terms and conditions of the lease deed and Minor Mineral Concession Rules, 1963. A further allegation was made in the show-cause notice that the petitioners have failed to pay some amount with regard to the fourth installment of the first year and first installment of the second year, thus, an amount of Rs.2,46,41,590/- was liable to be paid by the petitioners. The petitioners submitted a reply vide reply dated 8.3.2019.

5. It is further contended in paragraph 13 of the writ petition that on 16.4.2019, the petitioners addressed a communication to the respondent No.2 stating therein that the District Administration are completely non-co-operative and created various difficulties in running the excavation work by the petitioners. It is contended that without considering the reply submitted by the petitioners, respondent No.2 passed order dated 31.5.2019 cancelling the lease deed granted in favour of the petitioners and blacklisted the petitioners' firm for a period of five years and the respondent No.2 has also directed for recovery of Rs.3,37,38,653.30/- along with 10% amount payable on royalty and 2% TDS along with 18% interest per year.

6. After the aforesaid order dated 31.5.2019 was passed, a consequential recovery certificate dated 1/4.6.2019 was also issued against the petitioners for recovery of amount of Rs.3,97,87,185/- along with 2% TDS and 10% mineral development charges. The total amount payable by the petitioners as per the recovery certificate is Rs.4,79,72,794.17/-. The petitioners have filed the present writ petition challenging the order of blacklisting dated 31.5.2019 as well as recovery

Sumit
1/4 *SAL*
ACE

A

certificated dated 1/4.6.2019 issued by the respondent No.2, copies of which are appended as Annexure Nos.4 and 5 to the writ petition respectively.

7. It is contended by Sri Shashi Nandan, learned Senior Counsel that order dated 31.05.2019 passed by respondent No.2 is wholly illegal and arbitrary and has been passed without providing any opportunity of hearing to the petitioners. It is further contended that a reply of the petitioners dated 8.3.2019 was not at all taken into consideration, while passing the order dated 31.5.2019. It is further contended that the District Level Committee under the chairmanship of Additional District Magistrate was formed by the order of the District Magistrate on 11.3.2019 and the said committee submitted its report on 24.4.2019. It is contended that the report submitted by the Committee dated 24.4.2019 has formed the basis of the impugned order passed by the respondent No.2. However, the petitioners have never been provided copy of the said report before passing the order impugned dated 31.5.2019. It is further contended that the petitioners are entitled to get a copy of the report submitted by the District Level Committee dated 24.4.2019 before passing the order impugned. It is further contended that since the copy of the aforesaid report was not provided to the petitioners which was heavily relied upon by respondent No.2 while passing the order impugned, therefore, the order impugned is liable to be set aside only on account of non-supplying of the said report.

8. Heard learned counsel for the parties. With the consent of learned counsel for the parties, the present writ petition is disposed of at the admission stage itself without calling a counter affidavit from the respondents.

9. From perusal of the facts which are not disputed by the learned Additional Chief Standing Counsel, it appears that before passing the order of blacklisting, no opportunity of hearing whatsoever has been

Handwritten signature and initials
SRI SHASHI NANDAN
A.E.F.

Handwritten mark

provided to the petitioners. It is further not disputed that copy of the report submitted by District Level Committee dated 24.2.2019, which was relied upon by respondent No.2 while passing the order dated 31.5.2019, was never supplied to the petitioners. Although the order of blacklisting having serious civil consequences but in the present case before passing the same, no opportunity of hearing has been provided to the petitioners at any point of time. The law on the subject of blacklisting is well settled in light of numerous decisions of the Supreme Court on this subject.

10. In the case of *Erusian Equipment & Chemicals Ltd. Vs. State of West Bengal (1975) 1 SCC 70*, it was held by the Supreme Court that blacklisting has the effect of preventing a person from the privilege and advantage of name into relationship with the Government for purpose of aim. It was held by the Supreme Court in the aforesaid case that the fundamentals of fair play require that a person concerned should be given an opportunity to represent his case. Paragraphs 12 and 20 of the said judgment is quoted below:-

"12. Under Article 298 of the Constitution the executive power of the Union and the State shall extend to the carrying on of any trade and to the acquisition, holding and disposal of property and the making of contracts for any purpose. The State can carry on executive function by making a law or without making a law. The exercise of such powers and functions in trade by the State is subject to Part III of the Constitution. Article 14 speaks of equality before the law and equal protection of the laws. Equality of opportunity should apply to matters of public contracts. The State has the right to trade. The State has there the duty to observe equality. An ordinary individual can choose not to deal with any person. The Government cannot choose to exclude persons by discrimination. The order of blacklisting has the effect of depriving a person of equality of opportunity in the matter of public contract. A person who is on the approved list is unable to enter into advantageous relations with the Government because of the order of blacklisting. A person who has been dealing with the Government in the matter of sale and purchase of materials has a legitimate interest or expectation. When the State acts to the prejudice of a person it has to be supported by legality.

20. Blacklisting has the effect of preventing a person from the privilege and advantage of entering into lawful relationship with

Sanjay K. Singh
ASST

20

the Government for purposes of gains. The fact that a disability is created by the order of blacklisting indicates that the relevant authority is to have an objective satisfaction. Fundamentals of fair play require that the person concerned should be given an opportunity to represent his case before he is put on the blacklist."

11. Further in the case of *Gorkha Security Services Vs. Government of NCT of Delhi & Others (2014) 9 SCC 105*, the Supreme Court reiterated the principles laid down in the case of *Erusian Equipment & Chemicals Ltd. v. State of W.B. (supra)* and highlighted the necessity of giving an opportunity of hearing or show-cause before blacklisting him. Paragraph 17 of the aforesaid judgement is quoted below:-

17. Way back in the year 1975, this Court in Erusian Equipment & Chemicals Ltd. v. State of W.B. [Erusian Equipment & Chemicals Ltd. v. State of W.B., (1975) 1 SCC 70], highlighted the necessity of giving an opportunity to such a person by serving a show-cause notice thereby giving him opportunity to meet the allegations which were in the mind of the authority contemplating blacklisting of such a person."

12. Again in the case of *Raghunath Thakur Vs. State of Bihar [(1989) 1 SCC 229]* the aforesaid principles was reiterated in the following manner: (SCC p. 230, para 4).

"4. But it is an implied principle of the rule of law that any order having civil consequence should be passed only after following the principles of natural justice. It has to be realised that blacklisting any person in respect of business ventures has civil consequence for the future business of the person concerned in any event. Even if the rules do not express so, it is an elementary principle of natural justice that parties affected by any order should have right of being heard and making representations against the order. In that view of the matter, the last portion of the order insofar as it directs blacklisting of the appellant in respect of future contracts, cannot be sustained in law....."

20. Thus, there is no dispute about the requirement of serving show-cause notice. We may also hasten to add that once the show-cause notice is given and opportunity to reply to the show-cause notice is afforded, it is not even necessary to give an oral hearing. The High Court has rightly repudiated the appellant's attempt in finding foul with the impugned order on this ground. Such a contention was specifically repelled in Patel Engg. [Patel Engg. Ltd. v. Union of India, (2012) 11 SCC 257; (2013) 1 SCC (Civ) 445]."

Scanned by *Del*
ATG

4

13. In the case of *M/s Mahabir Auto Stores & Ors. Vs. Indian Oil Corporation Ltd.* (1990) 3 SCC 752 it was held by the Supreme Court that arbitrariness and discrimination in every matter is subject to judicial review. Paragraph 11 of the aforesaid judgement is quoted below :-

"It is well settled that every action of the State or an instrumentality of the State in exercise of its executive power, must be informed by reason. In appropriate cases, actions uninformed by reason may be questioned as arbitrary in proceedings under Article 226 or Article 32 of the Constitution. Reliance in this connection may be placed on the observations of this Court in M/s Radha Krishna Agarwal & Ors. v. State of Bihar & Ors., [1977] 3 SCC 457. It appears to us, at the outset, that in the facts and circumstances of the case, the respondent-company IOC is an organ of the State or an instrumentality of the State as contemplated under Article 12 of the Constitution. The State acts in its executive power under Article 298 of the Constitution in entering or not entering in contracts with individual parties. Article 14 of the Constitution would be applicable to those exercises of power. Therefore, the action of State organ under Article 14 can be checked. M/s Radha Krishna Agarwal v. State of Bihar, (supra) at p. 462, but Article 14 of the Constitution cannot and has not been construed as a charter for judicial review of State action after the contract has been entered into, to call upon the State to account for its actions in its manifold activities by stating reasons for such actions. In a situation of this nature certain activities of the respondent company which constituted State under Article 12 of the Constitution may be in certain circumstances subject to Article 14 of the Constitution in entering or not entering into contracts and must be reasonable and taken only upon lawful and relevant consideration, it depends upon facts and circumstances of a particular transaction whether hearing is necessary and reasons have to be stated. In case any right conferred on the citizens which is sought to be interfered, such action is subject to Article 14 of the Constitution, and must be reasonable and can be taken only upon lawful and relevant grounds of public interest. Where there is arbitrariness in State action of this type of entering or not entering into contracts, Article 14 springs up and judicial review strikes such an action down. Every action of the (1975) 1 SCC 70. State executive authority must be subject to rule of law and must be informed by reason. So, whatever be the activity of the public authority, in such monopoly or semi-monopoly dealings, it should meet the test of Article 14 of the Constitution. If a Governmental action even in the matters of entering or not entering into contracts, fails to satisfy the test of reasonableness, the same would be unreasonable. In this connection reference may be made to E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu & Anr., [1974] 4 SCC 3;

Prakash *DEL*
BGS

As

Maneka Gandhi v. Union of India & Anr., [1976] 1 SCC 248; Ajay Hasia & Ors. v. Khalid Mujib Sehravardi & Ors., [1981] 1 SCC 722; R.D. Shetry v. International Airport Authority of India & Ors., [1979] 3 SCC 1 and also Dwarkadas Marlaria and sons v. Board of Trustees of the Port of Bombay, [1989] 3 SCC 293. It appears to us that rule of reason and rule against arbitrariness and discrimination, rules of fair play and natural justice are part of the rule of law applicable in situation or action by State instrumentality in dealing with citizens in a situation like the present one. Even though the rights of the citizens are in the nature of contractual rights, the manner, the method and motive of a decision of entering or not entering into a contract, are subject to judicial review on the touchstone of relevance and reasonableness, fair play, natural justice, equality and non-discrimination in the type of the transactions and nature of the dealing as in the present case."

14. From perusal of the the aforesaid legal preposition, which itself is a reiteration of the principles laid down by the Supreme Court in *Erusian Equipment & Chemicals Ltd. v. State of W.B.* (*supra*), we are of the view that the petitioner could not have been blacklisted without being afforded an opportunity of hearing. It cannot be disputed that an order of blacklisting does carry serious civil consequences. It therefore follows as a necessary corollary that an adherence to the fundamental precepts of natural justice is essential and a prerequisite.

15. Since in the facts of the present case, there is a complete failure to follow due process, we find ourselves unable to sustain the order dated 31.05.2019 and the recovery certificate dated 1/4.6.2019 passed by the respondent No.2 (Annexure No.4 and 5 to the writ petition respectively)

16. We accordingly allow the writ petition and quash the the order dated 31.05.2019 and the recovery certificate dated 1/4.6.2019. We further clarify that in case the respondents do choose to initiate fresh proceedings for blacklisting the firm of the petitioner, we leave it open to them to do so subject to the observation that the proceedings if initiated shall be undertaken in accordance with law and the observations appearing herein above.

Order Date :- 8.7.2019
as/ajn

AUTHENTICATED COPY

SECTION OFFICER
COMPUTERISED COPYING SECTION
HIGH COURT, ALI AHABAD

Prakash
Del
Prisc

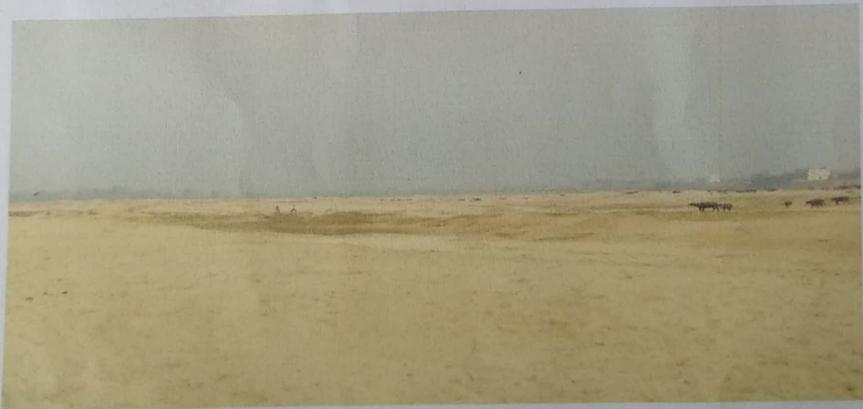
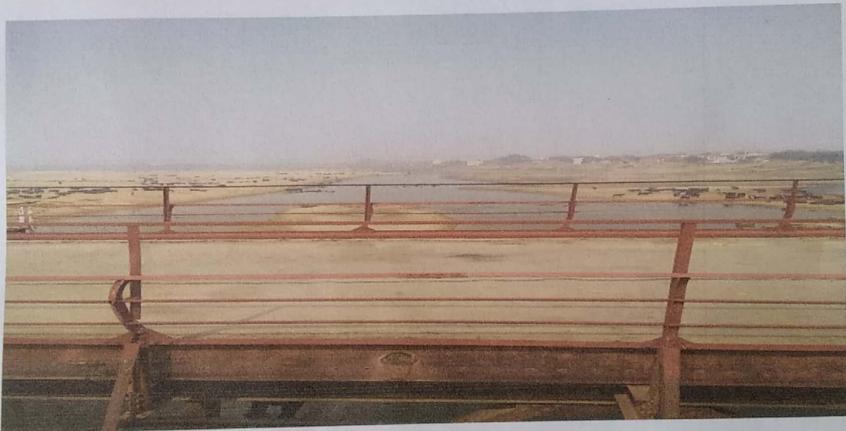
1

Photographs of River Garrah at district Shahjahanpur taken on dated 14-02-2020



Pravin Kumar Singh

Photographs of River Garrah at district Shahjahanpur taken on dated 14-02-2020



Signature *Signature*

Signature